

Area under paddy increases, but sugar crisis keeps farmers jittery

fe Bureau
New Delhi, May 15

With agencies predicting a sub-normal monsoon, summer sowing has begun on a modest note. According to the agriculture ministry data, till Friday, the planting of paddy crop has risen 20% y-o-y, but that of sugarcane fell 1%.

The area under paddy cultivation has risen to 1.80 lakh hectare till Friday against 1.5 lakh hectare last year. However, cane coverage dropped to 40.18 lakh hectares as of Friday against 40.58 lakh hectare last year.

Farmers moving to other crops due to crisis in the sugar sector, which led to cane arrears in excess of ₹21,000 crore, may be a reason for the fall in sugarcane plantation.

Since summer sowing has barely started, the data for

SEED OF HOPE



(Sowing in lakh hectare)

RICE

2014-15

1.50

2015-16

1.80

SUGARCANE

2014-15

40.58

2015-16

40.18



other crops are unavailable. Summer planting usually starts around mid-May and picks up with monsoon.

Late last month, the Indian Meteorological Department (IMD) had predicted monsoon

at 93% of the benchmark average — gloomier than the weather office's first long-range forecast last year. This year, it also lined up three probabilities — 28% for a normal monsoon, 35% for less

than normal shower and 33% for deficient.

Though monsoon is expected to hit the Kerala coast on May 30 from where it enters the mainland, it's still unclear how the monsoon will

progress after that. Moreover, if the geographical spread of the showers remains erratic, along with a lesser rainfall, sowing would be adversely affected.

While a normal monsoon is crucial to push the economic growth, given a weak investment climate, tepid export growth and fragile consumption, a Crisil Research note says a deficient monsoon, if it comes true, could shave off 50 basis points from the agency's GDP growth forecast of 7.9% for the current fiscal. However, Skymet Weather Services has predicted a rainfall at 102% of the long-period average and it also does not expect the El Niño condition, which is responsible for drought, to play out this year, although climate researchers abroad are predicting an enhanced probability of such a dreaded scenario in 2015.

Financial Express

16-5-15

उप्र सरकार की बेरुखी से संकट में चीनी उद्योग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के गन्ना बेल्ट में किसानों का असंतोष गंभीर आक्रोश में तब्दील हो रहा है। पिछले कई वर्षों से घाटे में डूब रहे चीनी उद्योग को उबारने की कोशिश नहीं हो रही है। गन्ना उत्पादक अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश शासन की अनदेखी और अदूरदर्शिता का खामियाजा यहां के गन्ना किसान और चीनी उद्योग को उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार की बेरुखी से चीनी उद्योग संकट में है।



◆ गन्ना बेल्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ असंतोष, बकाया 10 हजार करोड़ रुपए

दूसरी ओर केंद्र सरकार चीनी उद्योग की मुश्किलें सुलझाने और गन्ने का भुगतान कराने की जुगत में लगी हुई है। गन्ना उत्पादक राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह बनाकर दूरगामी नीति बनाने को कहा। समूह इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की असंवेदनशीलता का आलम यह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की बुलाई बैठक में खुद आने के बजाय अपना नुमाइंदा भेज दिया। जबकि गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर समस्या के समाधान के लिए मदद की गुहार लगाई। मराठा नेता शरद पवार ने भी पिछले सप्ताह मोदी से मिलकर चीनी उद्योग को उबारने के उपाय सुझाए। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने बताया कि गन्ना बकाया बढ़कर 21 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 10 हजार करोड़ रुपये है। पेरार्ड सीजन की शुरुआत में राज्य सरकार ने 40 रुपये प्रति क्विंटल की मदद का आश्वासन दिया था। टैक्स व उत्पाद शुल्क के रूप में 11.40 रुपये की रियायत को छोड़ दिया जाए तो 28.60 रुपये पर राज्य प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। अगर राज्य सरकार की ओर से इसका भुगतान हो जाए तो 2300 करोड़ रुपये का गन्ना बकाया तत्काल

दिया जा सकता है। वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की जगह उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) घोषित कर चीनी उद्योग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चीनी मिलों को बदतर हाल तक पहुंचाने में राज्य सरकार की भूमिका अहम है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए राज्य की अखिलेश सरकार ने केंद्र के घोषित गन्ना के एफआरपी 220 रुपये प्रति क्विंटल को नकार कर एसएपी 280 रुपये घोषित कर दिया। इसके विपरीत बाजार में चीनी लागत से कम मूल्य पर बिक रही है, जिससे मिलों का घाटा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर गन्ना भुगतान कराने और मिलों की दशा सुधारने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त कानूनी अधिकार हैं, जिसका प्रयोग किया जा सकता है। बालियान के मुताबिक केंद्र की पहल पर चीनी उद्योग के लिए ढेर सारी रियायतों की घोषणा की गई है। इनमें आयात शुल्क 25 फीसद से बढ़ाकर 40 फीसद, मिलों को ब्याज रहित ऋण और चीनी निर्यात पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। इसके विपरीत राज्य सरकार चीनी मिल मालिकों की सुनने को भी तैयार नहीं है।

Daimi Jagoram

12/5/16

✓ R